भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 817
23 जुलाई, 2026 को उत्तर देने के लिए

खाद्य तेल निष्कर्षण और प्रसंस्करण क्षमता

+817. श्री राजीव रायः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने घरेलू खाद्य तेल निष्कर्षण और प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी तिलहन प्रसंस्करण इकाइयोंकी स्थापना अथवा आधुनिकीकरण किया गया है; और

(ग) क्या मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) **:** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर, 2024 को घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास करने के लिए 10,103.38 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा 7,481.67 करोड़ रुपये) के परिव्यय के साथ नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स-ऑयलसीड्स (एनएमईओ-ओएस) को मंजूरी दी। मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक तिलहन के प्राथमिक उत्पादन को 69.7 मिलियन टन तक बढ़ाना, इसके अंतर्गत क्षेत्र को 33 मिलियन हेक्टेयर तक विस्तारित करना और उत्पादकता को 2,112 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक सुधारना है।

मिशन को बाज़ार जुड़ाव के साथ क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण से लागू किया जा रहा है। मूल्य श्रृंखला क्लस्टर का प्रबंधन किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओं), सहकारी समितियों और अन्य एजेंसियों जैसे मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा किया जाता है। इन क्लस्टरों के अंतर्गत, किसानों को 1 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए मुफ़्त उच्च गुणवत्ता वाले बीज और अच्छी कृषि पद्धतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, खाद्य तेल उत्पादन की क्षमता और दक्षता में सुधार के लिए तेल निष्कर्षण इकाइयों (10 टन क्षमता) और तिलहन प्रसंस्करण के लिए मशीनरी और उपकरणों हेतु परियोजना लागत के 33% की

दर से, प्रति इकाई अधिकतम 9.90 लाख रुपये तक की सहायता भी प्रदान की जाती है। वर्ष 2025-26 के दौरान मूल्य श्रृंखला क्लस्टर्स में मुफ़्त बीज वितरण के अंतर्गत अब तक 13.52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जबकि वार्षिक लक्ष्य 10.00 लाख हेक्टेयर है। इसके अतिरिक्त, एनएमईओ ऑयलसीड्स के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के दौरान 60 सीड हब, 50 विशेष बीज भंडारण इकाइयां और 400 तेल मिलें स्वीकृत की गईं।

देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाने, पाम ऑयल क्षेत्र के विस्तार, कच्चे पाम तेल (सीपीओ) के उत्पादन को बढ़ाने और खाद्य तेलों के आयात बोझ को कम करने के उद्देश्य से अगस्त 2021 में 'नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स-ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी)' नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई है। वर्तमान में, देश भर में 27 परिचालित ऑयल पाम प्रसंस्करण मिलें काम कर रही हैं।

(ख) और (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश भर में अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफ़पीआई), और केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफ़एमई) के माध्यम से, खाद्य तेल प्रसंस्करण इकाइयों सहित खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना की स्थापना और विस्तार की सहायता कर रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्र तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना है, जिसमें भंडारण, परिवहन, मूल्यवर्धन आदि शामिल हैं। इससे उत्पादकता बढ़ेगी, कृषि उपज की बर्बादी कम होगी, कटाई के बाद के नुकसान में कमी आएगी और प्रसंस्करण स्तर में वृद्धि होगी।

दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, पीएमकेएसवाई की एक घटक योजना, खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजनविस्तार/ (सीईएफपीपीसी) के अंतर्गत, वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान, खाद्य तेल प्रसंस्करण से संबंधित कुल 14 परियोजनाओं को 55.32 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान के साथ मंजूरी दी गई है। इसी तरह, पीएफएमई योजना के अंतर्गत, वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान, देश भर में तेल प्रसंस्करण से संबंधित कुल 10120 सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को मंजूरी दी गई है।

*****